

**Title:** Discussion regarding issue of National security and rise of militancy in various parts of the country especially in North-East and Jammu & Kashmir, raised by Shri Vilas Muttemwar on the 14th December, 1999. (Cont.- Concluded)

MR. SPEAKER: Now, let us take up discussion under Rule 193. Shri L.K. Advani to reply.

गृह मंत्री ( श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री विलास मुत्तेमवार और श्री राजेश पायलट को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ की है और सदन को यह अवसर दिया कि देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के लिये जो संकट देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पैदा हुआ है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करे सञ्जाव दे। मुझे इस बात की विशेष खुरशी है कि इस बहस में २३ माननीय सदस्यों ने कुल मिलाकर भाग लिया। हालांकि बहस का समय दो घंटे निर्धारित हुआ था लेकिन यह साढ़े चार-पांच घंटे बहस चली। मैं पूरे तौर पर कह सकता हूँ कि यह बहस रचनात्मक थी।

उसमें किसी ने भी कोई प्वाइंट स्कोर करने का नहीं सोचा कि इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया या उस सरकार ने वैसा किया। सब माननीय सदस्यों के भाषणों में तीन चीजों लगभग समान थीं, पहली चीज कि संकट गंभीर है, उसे कम नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज उसमें एक सामूहिक संकल्प भी उभरता था कि हमें हर स्थिति में इस संकट का निवारण करना चाहिए, देश को इसके ऊपर उभरना चाहिए और तीसरी चीज यह भी बार-बार उभरती थी कि यह सबाल ऐसा नहीं है कि जिसे दलगत दृष्टि से सोचा जाए। हम मिलकर इस बारे में सोचें, मिलकर इसका निवारण करें। वैसे तो यह सारे देश की चर्चा है, लेकिन प्रस्ताव देने वालों

particularly in Jammu and Kashmir and in the North-East

इन दोनों हिस्सों से मैं अलग-अलग डील करूंगा। पहले मैं जम्मू-कश्मीर की चर्चा करूंगा उसके बाद मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा करूंगा। मैं मानता हूँ कि इस शताब्दी के सात-बे दशक तक आतंकवाद से हम परिचित नहीं थे। देश में आतंकवाद नहीं था। कहीं-कहीं हिंसा थी। उत्तर-पूर्व के हिस्सों में कहीं-कहीं हमने इनसर्जन्सी का मुकाबला किया है। लेकिन आतंकवाद जिसमें बेगुनाह लोगों की हत्या चाहे जब कर दो, बम विस्फोट कर दो, रास्ते चलते किसी की हत्या कर दो या चुन-चुन कर कुछ लोगों को मार दो। इस प्रकार की स्थिति सात-बे दशक तक लगभग नहीं थी। मैं कभी-कभी अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करता हूँ जब मैं पहली बार सरकार का हिस्सा बना, श्री मोरारजी भाई उस समय प्रधान मंत्री थे, मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। मेरा जन्म-स्थान कराची है, मैं वहाँ का निवासी रहा हूँ। इसलिए जब मुझे उनका निमंत्रण मिला तो मैं वहाँ गया था। उस समय वहाँ सैनिक शासन था, जैसा कि आज है। कराची शहर में चारों ओर सेना की टुकड़ियाँ दिखाई देती थीं। जनरल जिया उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे। मैं वहाँ दो दिन था। स्वाभाविक रूप से मुझसे वहाँ के राजदूत पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं अपने निवास-स्थान और अपने स्कूल जाना चाहूँगा। अपनी पुरानी स्मृतियाँ सजीव करने के लिए मैंने उनका उल्लेख कर दिया। मेरे साथ पाकिस्तान का अधिकारी था, जो मेरे साथ चलता था, जहाँ के लिए भी मैं कहता था वह साथ चलता था। जब मैं वहाँ सहज रूप से घूम रहा था तो कई लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया यह भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री हैं। उनको तान्जुब होता था कि उनके यहाँ तो इतनी सेना, इतनी सुरक्षा होती है। यह १९७८ या अरली १९७९ की बात होगी। उन्हें आश्चर्य होता था कि भारत का केंद्रीय मंत्री बिना सुरक्षा के यहाँ घूम रहा है और हमारे यहाँ जितने सांसद, विधायक और मंत्री हैं वे पूरा का पूरा पैराफर्नैलिया लेकर घूमते हैं। यह १९७७ की बात है और जब आज सोचता हूँ तो अब कितना अंतर हो गया है। आज मेरे साथ ब्लैक कैट कमांडोजे जाते हैं, सांसदों के साथ कई सुरक्षाकर्मी जाते हैं। कई-कई प्रदेशों में तो हर एक विधायक के साथ सुरक्षा लगाई गई है। ऐसी स्थिति है, जिसके कारण यह बात उभरकर आती है कि आंतरिक सुरक्षा के वातावरण में पिछले दो दशकों में जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। मैं समझता हूँ कि वह शायद अजीत चौधरी थे, उनका अपने भाषण के आखिर में जो बयान था, वह मैं सुन रहा था। उन्होंने उल्लेख किया था

The genesis of militancy in Jammu and Kashmir lies in the 1971 war

ऐसा ही कुछ आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं सचाई बताना चाहूँगा, जो कुछ उन्होंने कहा, वह एक प्रकार से सही विश्लेषण है। १९७१ में पाकिस्तान की जो भारी पराजय हुई, उसने पाकिस्तान को सोचने के लिए मजबूर किया कि रणभूमि में भारत की सेना के साथ मुकाबला करना सहज नहीं है और फिर उन्होंने अपने मिलिट्री जनरलों के साथ बैठकर रणनीति बदली और रणनीति बदलते हुए, जो उनका विचार-विमर्श हुआ, कहीं कुछ अखबारों में छपा है, जनरल जिया उल हक ने अपने मिलिट्री कमांडरों से बात कर के कहा कि अब हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और उसके तहत एक 'टोपेक' नाम से कार्रवाई करना निश्चित किया गया। यह भाषण १९७३-७४ का भाषण है, लेकिन उसकी तैयारी करते-करते और उसे क्रियान्वित करते-करते उनको समय लग गया। ८०वें दशक में

In the eighties, it was implemented or executed

और योजनाबद्ध रूप से उन्होंने पंजाब से शुरू किया।

श्री श्यामाचरण शर्मा (महासमुद्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आडवाणी जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वे इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तान ने १९८५, १९८६ और १९८७ के आसपास से बेधड़क, निडर होकर के मिलीटरी को बढ़ाया, चाहे पंजाब हो या जम्मू-कश्मीर।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं, इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा अपना विश्लेषण है कि यह शिमला एग्रीमेंट के बाद, पाकिस्तान ने हमसे जो कुछ कहा, उसके विपरीत काम करते हुए, न्यूक्लीयर बम की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया।

This was part of an overall strategy.

शिमाल एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ-

I do not want to score points today, I want to simply point out that.

उसके बाद प्राकसी वार का जन्म हुआ। वह १९७१ के युद्ध में से हुआ और प्राकसी वार में जब पाकिस्तान को चोट लगनी शुरू हुई और उनको एक प्रकार से लगा कि पाकिस्तान प्राकसी वार में भी सफल नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी धीरे-धीरे भारत अपना अंकुश जमा रहा है। तब उसमें से कारगिल की उत्पत्ति हुई। कारगिल में से प्राकसी को वार तीव्र कर, आतंकवाद को आगे बढ़ा।

So, all the steps of Pakistan result from failure and frustration, not from confidence and hope.

जितनी प्राकसी वार पहले थी, १९७१ में जो पाकिस्तान को विफलता मिली, उसकी पराजय हुई और जब वे प्राकसी वार में भी सफल नहीं हुए, तो कारगिल का जन्म हुआ और जब कारगिल में विफल हुए, तो इन दिनों जो हिंसा हम देख रहे हैं, वह उसमें जन्मी है। जो बादामी बाग और इधर-उधर घटनाएँ हो रही हैं, ये उसी का परिणाम हैं। ये कभी बन्द नहीं हुई हैं। मैं आंकड़े भी देखता हूँ, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर कभी दावा नहीं करूँगा कि उनके आतंकवादियों की मृत्यु ज्यादा हो रही है और हमारे लोगों की कम, मैं यह नहीं कहूँगा। मैं मानता हूँ कि युद्ध में भी हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि प्राकसी वार में हुआ। इसलिए मुत्तेमवार जी ने कहा कि हमारे जितने लोग प्राकसी वार में मारे गए उतने प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं मरे। मेरे पास पिछले १० साल के आंकड़े हैं। उनके अनुसार निरीह नागरिक, सिविलियन्स ७,९६० मरे हैं।

I am simply counting the number of toll from 1988-89 onwards.

मिलीटेंट को सिक्खोरिटी वाले मारते रहे हैं।

Ten thousand seven hundred and twenty seven militants had been killed during the same period though the cost that we have had to bear is the death of 2,039 securitymen.

२०३९ सिक्खोरिटी मैन हमारे मारे गये। उनका कोई सिक्खोरिटी मैन नहीं मारा गया। अप्रत्यक्ष युद्ध, प्रॉक्सि वार का जो सबसे बड़ा नुकसान है, वह यह है कि

It is our securitymen, our Jawans, our Armymen, our paramilitary forces" men who are being killed and not one from the Pakistan side. On the other hand -

युद्ध होता है तो उसमें हमारे ४०० लोग कारगिल में मारे गये तो उनके ६०० मारे गये और सब सिक्खोरिटी मैन मारे गये। उनके भी सिक्खोरिटी मैन मारे गये। उनके कोई मर्सीनरीज नहीं थे। ये सब प्रायः मर्सीनरीज थे। अच्छी बात अगर कोई है, राजेश जी ने उल्लेख किया कि एक बार राजीव जी ने कहीं कहा कि हम कहीं १९९० में वापिस तो नहीं पहुंच जायेंगे। मैं यह मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद हुआ है, उसमें

The worst years were 1989, 1990 and 1991. These were the worst years. But that phase continued for a long time.

यहां तक कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी, उसमें आजीविका का प्रमुख आधार है, वह पर्यटन है, टूरिज्म है।

Tourism has absolutely dried up.

मेरे पास टूरिज्म के आंकड़े हैं, जो कि आश्चर्यकारक हैं। १९९५ में सारे भारतवर्ष से डोमेस्टिक टूरिस्ट ३२२ गये। १९९६ में ३७५, १९९७ में ७०२९, १९९८ में ९९,६३६ और १९९९ में १,९४,३२ टूरिस्ट गये हैं। मैंने १९९९ के जो आंकड़े बताये उनमें मैं १,१०,३४५ अमरनाथ के यात्रियों को नहीं गिन रहा हूँ। उनमें वैष्णो देवी जो ४ लाख यात्री गये हैं, उनको मैं नहीं गिन रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि यह जो मापदंड है। वहां की स्थिति नार्मसी की ओर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसको मापने का

This is a more correct barometre rather than the number of people killed.

कितने लोग मारे गये, कितने लोग नहीं मारे गये, मैं उससे ज्यादा इसको पैरामीटर मानता हूँ क्योंकि सेंस ऑफ सिक्खोरिटी जब होगा तभी लोग जायेंगे, नहीं तो नहीं जायेंगे। जैसे ३२२ लोग एक साल में गये हैं। ३७५ लोग एक साल में गये हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उन ईयर्स में मैंने देखा कि पहले विदेशी आते थे, देशी नहीं जाते थे। लेकिन जब से एक घटना हुई जिसमें अलग-अलग देशों से आये हुए पांच विदेशियों का अपहरण कर लिया गया और वे गायब हो गये, नहीं मिले। आज तक उनके रिश्तेदार आकर मुझे मिलते हैं। उनके एम्बेसेडर आकर मिलते हैं। हम उन्हें नहीं खोज पाये और हो सकता है कि वे बचे भी न हों, खत्म हो गये हों। लेकिन यह जो एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार पर विश्वास होता है कि चाहे संकटपूर्ण स्थिति है, चाहे हिंसा आज भी है। हम हिंसा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाये हैं लेकिन हम इसके ऊपर विजय अवश्य पायेंगे, यह एक विश्वास मन में है और वह विश्वास उस विश्वास का एक आधार है हमारा अपना पंजाब का अनुभव। एक समय था जब पंजाब में, मैं कई बार जाता था और लगता था कि यहां तो कुछ बदलेगा नहीं। यहां कुछ परिवर्तन आयेगा नहीं। यहां तो सालों साल तक ऐसे ही चलेगा। शाम को सड़कें सुनसान हो जाती थी और घर से कोई नहीं निकलता था। लेकिन परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि मैंने उत्तर पूर्व के भाई यहां बैठे हैं, जो हमेशा मुझसे आकर आग्रह करते हैं कि पैरामिलिटरी फोर्सस भेजो, सेना भेजो, यह भेजो आदि। मैं सबको कहता हूँ कि पंजाब का अनुभव इस बात को बताता है कि उग्रवाद के ऊपर अगर विजय पानी है, तो यह सहायक होगा। आर्मी सेना सहायक होगी, अर्द्ध सैनिक बल सहायक होगा। मुख्यतः वहां की जनता, उस प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की पुलिस यह जो तीन तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर विजय प्राप्त होगी और इसका जम्मू कश्मीर से भी संबंध है। जितनी मात्रा में हम वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां की स्थानीय पुलिस उसको इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम इसका मुकाबला करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, उतनी मात्रा में सफलता मिलेगी।

इस सफलता में केन्द्र सरकार की सेना और पैरा-मिलिट्री पुलिस सहायक होगी। लेकिन केवल केन्द्र सरकार की सेना और पैरा-मिलिट्री फोर्स के आधार पर इस संकट का निवारण संभव नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कहूँ चाहे उत्तर पूर्व की बात कहूँ, मैं मानता हूँ कि इन दिनों में सबसे अच्छी स्थिति जो हुई है, वह यह है कि १९८९-९०-९१ के प्रारंभिक वर्षों में जितने उग्रवादी थे, वे प्रायः वे थे जिनको पाकिस्तान, आई.एस.आई. के लोग जम्मू कश्मीर से ले जाकर, वहां प्रशिक्षण देकर वापिस भेजते थे। धीरे-धीरे जो लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों को ले जाने की बात है, वह खत्म होती गई। विगत वर्षों में जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, मारे जाते हैं, प्रायः वे जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, बहुत कम परसेंटेज है, अधिकांश परसेंटेज पाकिस्तान, अफगानिस्तान का है, और भी कई देशों का है। कभी-कभी मैंने किसी सवाल के उत्तर में बताया होगा कि कितने-कितने लोग किस-किस देश के थे जिनको मारा गया।

But all of them are mercenaries recruited by Pakistan to be sent here as cannon fodder.

भेजो उनको, मरवाओ उनको। इसलिए हमारी सेना के लोग भी कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारे सिक्खोरिटीमैन मरते हैं, उनके नहीं मरते। लेकिन अच्छा लक्षण यह है कि हमारे यहां से लोग नहीं जाते, कम जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी संख्या कम होती गई है। जितनी मात्रा में यह होगा उतनी मात्रा में हमको सफलता मिलेगी। यही चीज मैं उत्तर पूर्व के लिए भी कह सकता हूँ। विगत वर्षों में खासकर असम में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर नागरिकों ने उग्रवादियों का विरोध किया है और उग्रवादियों को पकड़कर लिंच किया है। सार्वजनिक रूप से विरोध तो किया ही है, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। मेरे पास अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं, सूचनाएं मिली हैं जिसमें कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। दुबरी डिस्ट्रिक्ट में दो घटनाएं हुईं, बरपेटा में दो घटनाएं हुईं, कामरूप में दो घटनाएं हुईं, नलबाड़ी में हुईं, उदयगिरी नाम के एक स्थान में हुईं। मेरे सामने इस प्रकार की आठ अलग-अलग घटनाएं आई हैं जहां पर आम जनता ने सार्वजनिक रूप से हिंमत करके, साहस करके उल्फा के आतंकवादियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया है, क्षोभ प्रकट किया है। हम यह स्थिति जितनी बढ़ा सकेंगे उतना इस मामले में सफल होंगे।

राजेश जी ने एक बात कही, पता नहीं क्यों कही। उन्होंने कहा कि हम पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर में अंतर क्यों करते हैं। नहीं करते। हम सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर जैसे पंजाब को देते थे वैसे आज जम्मू कश्मीर को भी देते हैं। कहीं-कहीं पर थोड़ा विवाद होता है कि सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर किसको माना जा सकता है। वह विवाद हम तय कर लेते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमने आज तक जम्मू कश्मीर राज्य को सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर के नाम से लगभग १४९८ करोड़ रुपये दिए।

... (व्यवधान)

मैंने बताया कि अगर कोई विवाद है तो वह इस बात पर है कि इसको सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर माना जाए या नहीं और उसे हम सांट आउट कर लेते हैं। हमने इसी साल सिक्खोरिटी रिलेटेड एक्सपैडिचर के नाते १८ करोड़ रुपये दिए हैं। वैद्य विष्णु बोले थे और उन्होंने कहा था, सही कहा था कि हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल के अलावा आज आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए जो विलेज डिफेंस कोर बनी है, वह बहुत इफैक्टिव है।

उनको और बढ़ाने की उन्होंने जरूरत महसूस की। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और उनको जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि खर्च उस समय प्रदेश की सरकार करती है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसको रीअम्बर्स करती है। जब इन वी.बी.सीज़. को बनाने का निर्णय हुआ था तो १२८८५ वी.बी.सीज़. की संख्या थी, लेकिन हमने उनको कनबे किया है कि हम १८,००० वी.बी.सीज़. का खर्च भी रीअम्बर्स करेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट से अनेक सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी है। नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, पश्चिम बंगाल के भी चार सदस्य बोले थे। कृष्णा जी जब बोली थीं कि हमारे यहां पर भी आई.एस.आई. का संकट है और उसकी चिन्ता करनी चाहिए। मैं उनको कह सकता हूँ कि यह जो चिन्ता उन्होंने प्रकट की, वैसी ही चिन्ता उनके प्रदेश के गृह मंत्री ने आकर मुझसे प्रकट की। वे कुछ ही दिन पहले मेरे पास आये थे और कहा कि आप जब आई.एस.आई. की चर्चा कर रहे थे, आंतरिक सुरक्षा के लिए आई.एस.आई. ने जो संकट पैदा किये हैं, उनका निरूद्ध कर्तव्य है तो आपके सार्वजनिक वक्तव्यों में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख होता है, पंजाब का उल्लेख होता है, नॉर्थ ईस्ट का उल्लेख होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं होता है। मैं आपको यह कहने आया हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी यह समस्या गम्भीर है और उसमें केन्द्र की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों सहकार करके, मिलकर उसका मुकाबला करें, यह बल देने आये थे। मैंने उनको कहा कि मैं तो आपके कथन का स्वागत करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में इस सरकार ने देश भर में और विदेश में भी एक वातावरण पैदा करने की एक प्रामाणिक कोशिश की है और यह कहा है कि यह समस्या केवल किसी राज्य की नहीं है। क्रास बोर्डर टैरिज्म का अगर हम सामूहिक रूप से विश्व भर के सभी देश मुकाबला करने के लिए मन नहीं बनाएंगे और सोचेंगे कि ठीक है, यह भारत की समस्या होगी, इसमें समस्या का कारण कश्मीर है, इसके कारण पाकिस्तान कुछ कर रहा है, उसकी ओर उदासीन होंगे तो उसका खमियाजा विश्व भर को भूगतना पड़ेगा, सारी दुनिया को भूगतना पड़ेगा, यह हमने विश्व भर में बोलने की कोशिश की है। मैं कह सकता हूँ कि देश में भी इसी प्रकार की जागृति पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं तो देख रहा था कि इन पिछले दो सालों में इतने सवाल माननीय सदस्यों की ओर से आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आये हैं। उसके पहले की लिस्ट निकालो तो १९९१ से लेकर १९९७ तक मैंने देखा कि बहुत कम सवाल हैं और यह अच्छी बात है और इसी कारण जब एक बार गृह मंत्रालय की कन्सल्टेटिव कमिटी की मीटिंग हुई थी तो उस कन्सल्टेटिव कमिटी की मीटिंग में दो घंटों का पूरा इंजंक्शन हमारे विभाग ने, गृह मंत्रालय ने किया था कि आई.एस.आई. ने किस प्रकार अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई हैं। उसको देखने के बाद सभी सदस्य नितने वहाँ पर उपस्थित थे, सोमनाथ बाबू वहाँ पर उपस्थित थे, बनातवाला जी उपस्थित थे, सब ने उसी समय कहा, यह कल्पना आई कि इस प्रकार की चीज देश के सामने रखनी चाहिए और वहाँ पर मांग थी, शायद बनातवाला जी ने मांग की कि इस पर व्हाइट पेपर प्रकाशित होना चाहिए। वह व्हाइट पेपर प्रकाशित करने का विचार सरकार का है। उसमें कुछ कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन वह शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा और आपके सामने रखा जायेगा। इतना मैं कह सकता हूँ।

उत्तर पूर्व में जैसे तो सात राज्य माने जाते हैं

... (व्यवधान)

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हम टैरिस्ट स्टेट घोषित करने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पाकिस्तान को टैरिस्ट स्टेट घोषित करें तो उसकी टैरिस्ट स्टेट की घोषणा का असर अमेरिका पर होगा, क्योंकि उनके अपने कानून हैं। इसकी मांग तो बहुत समय से होती रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्रास बोर्डर टैरिज्म के बारे में पहली-पहली बार अमेरिका की तरफ से अगर कोई टिप्पणियाँ हुई हैं तो इसी १९९९ में हुई हैं। इससे पहले तो कोई उसको रिकगनाइज़ करने को तैयार नहीं था। उसको यह मानते थे कि ठीक है, यह तो चलता है, आपकी तरफ से भी होता होगा, उनकी तरफ से भी होता है,

they never took notice of it.

इस बार मुझे याद है कि कारगिल के बाद जो घटना हुई। उसमें पहली बार सार्वजनिक रूप से अमेरिका की ओर से भी उस पर टिप्पणी की गई।

उसकी आलोचना की गई, निन्दा की गई। इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है, लेकिन मैं मानता हूँ, कुल मिलाकर अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, तो अपने बलबूते पर करेंगे, जनता के समर्थन से करेंगे। विदेशी ताकतों और अन्तर्राष्ट्रीय जनमत सहायक जरूर होगा और सहायक करने के लिए हमारी तरफ से कोई कसर हम उठाकर नहीं रखेंगे, लेकिन कोई दूसरा देश उस देश को टैरिस्ट स्टेट घोषित करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर हमारी सफलता या विफलता निर्भर नहीं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है, सात राज्यों की नार्थ-ईस्ट काउन्सिल बनी हुई है, लेकिन सरकार का विचार है कि सिक्किम को भी इसमें जोड़े। कुल मिलाकर नार्थ-ईस्ट में आठ राज्य हैं। इन आठ राज्यों में चार राज्य ऐसे हैं, जहाँ पर अपेक्षाकृत शान्ति है। वहाँ पर उग्रवाद, आतंकवाद इस रूप में नहीं है, जैसा कि बाकी चार राज्यों में है। ये चार राज्य हैं - मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय। इन चार राज्यों में, मैं मानता हूँ, अपेक्षाकृत शान्ति है। लेकिन बाकी चार राज्यों अर्थात् असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में स्थिति दूसरी है। नागालैंड में आज सीज-फायर नाम से समझौता हुआ है,

NSCM(I.M.)

और भारत सरकार के बीच। हम आए, उससे पहले हुआ था। वह सीज फायर जारी है और यह थोड़े-थोड़े काल के लिए होता है, लेकिन अब साल भर के लिए चला है। कल नागालैंड के माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं, उनमें वजन है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सीज फायर के जो ग्राउन्ड रूल्स बने हैं, उन ग्राउन्ड रूल्स का उल्लंघन होता रहा है। उनका उल्लंघन न हो और इस बात की व्यवस्था हमारे सुरक्षा कर्मों करें, यह उनको निर्देश दिया गया है। उस दिशा में हम चिन्तित हैं और गम्भीर हैं। पिछले दिनों हमारे नागालैंड के मुख्यमंत्री को एम्बुश करके जिस प्रकार की घटना हुई, वह अत्यन्त गम्भीर घटना है, जिसका हमने नोटिस लिया है। स्वयं माननीय सदस्य ने अपनी सुरक्षा के बारे में कहा है। सुरक्षा की बात मैंने गृह मंत्रालय के बताई है और उसका उपयुक्त प्रबन्ध हो जाएगा।

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): Mr. Speaker, Sir, could I just seek a clarification from the hon. Home Minister? Since this is directly related to the State of Nagaland, which I represent, I would like to seek a clarification.

Sir, an attempt on the life of the hon. Chief Minister of Nagaland was made on the 29th. I would like to ask him about the findings of the investigations made on the case by the Ministry of the Home Affairs. What kind of action is being proposed against the culprits and what measures are being adopted to protect the lives of the leaders of Nagaland who have been targeted a number of times in the past?

Sir, again, this morning I was reading a reply ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let the hon. Minister complete his reply and then you can ask clarifications on that.

SHRI L.K. ADVANI : I am not merely dealing with Nagaland here. I picked up the two points mentioned by you. I have noted that. If there is any separate question, then certainly I would answer that.

हमारे असम के माननीय सदस्य, श्री बैसीमुथियारी, ने बहुत बार आग्रहपूर्वक एक अलग बोर्डोलैंड बनाने की बात कही है। वे इसका आग्रह करते आए हैं, लेकिन कल उन्होंने एक बात कही, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। वह बात यह है कि जो उग्रवादी भारत से अलग होने की बात करते हैं, वे उनका विरोध करते हैं और वे इस प्रकार की सिसेशन प्रवृत्ति के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। अलग राज्य बोर्डोलैंड बनाने में उनके कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों के वे स्वयं जानते हैं, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों के कारण १९९३ में एक समझौता हुआ, जिसको बोर्डो-एकार्ड कहते हैं। बोर्डो एकार्ड के इम्प्लीमेंटेशन में कमियाँ हैं। इसकी चर्चा मुझे करते रहे हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बोर्डो की जनसंख्या नितनी है और जिस प्रकार से वह फैला हुआ और जिस भाग को वे बोर्डोलैंड बनाना चाहते हैं, वह अलग प्रदेश भी बन जाएगा,

उसमें भी बोडो की संख्या शायद ३०-३५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं बनती।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Excuse me, Sir, but I strongly oppose this argument. This is not at all correct.

MR. SPEAKER: The Minister has not yielded. Please sit down.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे किसी तर्क को न मानने का आपको पूरा अधिकार है। पहली बात यह है कि सिसैशन का विरोध सारे सदन ने किया। उसमें हमारे बोडो क्षेत्र के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि उनकी समस्याओं का हल भी चर्चा से निकलेगा, आतंकवाद से नहीं निकलेगा। अगर कोई सरकार गोली और बंदूक की भाषा सुनती है तो वह देश का भला नहीं करेगी। इसलिए मैं वार्ता करने के हमेशा पक्ष में हूँ, लेकिन वार्ता इस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए कि ऐसा लगे कि वह वार्ता बम और गोली की संस्कृति का परिणाम है। वार्ता करनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। आज अगर मिजोरम में शांति है तो उसका कारण यह है कि वार्ता उस सूरत में हुई, जब बहुत लोगों को लगा कि बम से, गोली और हिंसा से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी सरकार केंद्र में आए उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वार्ता की सदैव तत्परता रखते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वार्ता किन परिस्थितियों में की जाए, किन परिस्थितियों में न की जाए और किस के साथ की जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा यह संदेश जाए कि गोली और बम के कारण किसी को अपने राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, यह कम से कम सरकार स्वीकार नहीं करेगी।

... (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, may I seek a clarification from the hon. Minister regarding what he said about Assam.

MR. SPEAKER: Not now please.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की चर्चा लगातार चलती रही है। मुझे वहाँ के राज्यपाल ने सूचित किया कि उनकी भी चर्चा होती रही है। हम समझते हैं कि उनकी जो समस्याएँ जायज हैं, उनका निराकरण हम कर लेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What is the problem, Sir. Officials are not the decisive authorities to deal with the Bodoland issue. It is the political leadership which has to deal with this issue with positively for finding out means and ways to resolve the issue politically on a permanent footing.

SHRI L.K. ADVANI: I agree with you.

त्रिपुरा के बारे में हमारे समर चौधरी जी ने चिन्ता प्रकट की, उसमें मैं भी भागीदार हूँ। वहाँ बहुत सारे निरीह नागरिकों की हत्याएँ हुईं और बहुत सारे अपहरण हुए हैं। यह समर जी को मालूम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चार-पांच प्रमुख अधिकारी अगस्त से गायब हैं, उनका आज तक पता नहीं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, इन दोनों ने मिल कर प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुझे पिछले दिनों त्रिपुरा के मुख्य मंत्री मिले थे और प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। अगर कहीं यह धारणा है कि उसमें केंद्र सरकार की फोर्स की कमी के कारण है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं देख रहा था, ... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, I had the opportunity to go there on a visit. After my visit, I submitted a report to the Prime Minister. I wrote to the Home Minister also. It is an open border of 895 kilometres which is not there even in Punjab. It is a very sparsely populated State because of its terrain. Near the border, they go to Bangladesh in no time and people are able to see it. People cannot go to Bangladesh, 30 camps are being run in Bangladesh. They are coming and going with great ease. There are plain areas also there and Bangladesh is just across the road.

I fully agree with the view that people should resist it. But this facility should also be provided. Security forces are necessary. It is a very small State with a population of three million people.

15.00 hrs.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सोमनाथ जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे मानता हूँ। यह भूगोल है, इस पर दो मत नहीं हो सकते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, त्रिपुरा में १९९५ में सीआरपीएफ की ३० कंपनियाँ थीं लेकिन आज १९९९ में वहाँ पर ७५ कंपनियाँ हैं। यह ठीक है कि कारगिल के समय में वहाँ से हमने कुछ कंपनियाँ हटायी थीं। लेकिन आज प्री-कारगिल से भी बेहतर स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी कठिनाइयाँ हैं और कठिनाइयाँ इस कारण हैं कि

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): I was also dealing with Tripura. I request the hon. Minister to deploy Assam Rifles there because it is the most effective force for Tripura.

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहाँ सीआरपीएफ को कोई नहीं चाहता।

SHRI L.K. ADVANI: Shri Sontosh Mohan Dev may be aware that Assam Rifles are under the overall control of the Army and I cannot deploy them there.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : You can request for it.

SHRI L.K. ADVANI: I have already requested, but they also have their own problems. Because of those problems, today they have been able to perhaps spare 18 companies of the Assam Rifles. Eighteen companies are still deployed there in Tripura.

SHRI SAMAR CHOUDHURY (TRIPURA WEST): But now, they are not there. Earlier, once that deployment was there. But Army has already been lifted and shifted from Tripura. One Army cantonment was there earlier but that is completely dry. Now, not a single battalion of army security force is there who can defend Tripura. Assam rifles were also reduced. This is the position there.

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वहाँ जाकर एक दफा स्थिति देखिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ठीक है, मैं जाकर भी देखूंगा। अभी मेरी चीफ-मिनिस्टर साहब से विस्तार से बातचीत हुई। हमारे जो ऑफिसर इस मामले को डील करते हैं वे वहां स्थिति देखकर आये हैं। हमारी फोर्सिंग भी अगर किसी तरह ध्यान दे रही है तो उसमें जम्मू-काश्मीर के बाद त्रिपुरा है, जहां पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं जानता हूँ वहां का भूगोल जैसा है, सीमाएं जैसी हैं। वहां पर बंगला देश, नेपाल और सीमावर्ती देशों में आईएसआई ने जिस प्रकार से अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिशें की हैं। हमने सब ओर मल्टी-प्रोग्रेंड कोशिश की है। नेपाल, बंगलादेश, बर्मा और भूटान से भी हमारी इस विषय में बातें होती हैं कि किस प्रकार इस पर अंकुश लगाया जाए।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : वे तो भूटान में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आज से ६ साल पहले वे सारी की सारी गतिविधियां असम से ही चलाते थे। लेकिन वहां उनका समर्थन कम होता गया। इसलिए उनको असम छोड़कर और कहीं शरण लेनी पड़ी। भूटान से हमारी बातें चलती रहती हैं। अध्यक्ष जी, मैंने चाहे बल सुरक्षा बलों पर दिया होगा लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की ओर ध्यान देना और साथ-साथ विकास की ओर ध्यान देना, ये दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं। कभी किसी एक की उपेक्षा नहीं हो सकती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संबंध में मैं घोषणा करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री जी से बात हुई है कि जनवरी के मध्य में २० या २१ जनवरी को एक नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के सभी मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यपालों की एक कांफ्रेंस ईस्टर्न थीम को कंसिडर करने के लिए 'सुरक्षा और विकास' नाम से हम करने वाले हैं।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What about political solution, Sir?

SHRI L.K. ADVANI: Yes, there will be a political solution.

MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI: Even about their problems, there can be only political solutions and except that no other solution is there. But those political solutions should be brought about in a manner as not to put a premium on violence and the extremism.

पिछले दिनों आई.एस.आई. की काफी चर्चा हुई। मैं साथ-साथ एकाउन्ट लेता गया कि एक्यूअली क्या होता है? मुझे यह कहते खूशी है कि पिछले डेढ़-दो वर्षों में कुल मिला कर जिस को इंटेलिजिंस की भाषा में मांड्युल्स कहते हैं, ऐसे ४५ आई.एस.आई. बैकड मोड्युल्स डिटेक्ट किए और उनको स्मेश किया। इन्हें ४५ गिराए कइ सकते हैं। उन्हें अड्डा कहना ठीक नहीं होगा। अड्डे का संबंध स्थान से है। ४५ गिराए जो आई.एस.आई. ने संगठित किए, उनको खोज कर, समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। इस सारे प्रोसेस में शायद ११६ लोग गिरफ्तार किए गए और ८ लोग ऑपरेशन में मारे गए। इसके आधार पर मन में विश्वास होता है जो राष्ट्रपति जी ने देश और संसद के सामने सार्वजनिक रूप से सरकार की नीति की घोषणा की। उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस डिक्लरेशन किया।

It is stated as follows in paragraph 34 of the Address of the President of India on October, 25th: -

"The Prime Minister has announced that Government will follow the principle of "Zero Tolerance" while dealing with terrorism. Simultaneously, Government will continue to focus international attention on the deadly impact of trans-border terrorism that has claimed countless lives all over the world. There is no dearth of evidence how state-sponsored terrorism has affected peace and stability in South Asia and beyond. India is actively working to initiate concerted international opinion and action against state-sponsored terrorism in any part of the world. The menace of illicit drug trafficking, money laundering, and narco-terrorism has also to be effectively countered through both national and international efforts."

हमने इस वक्तव्य में अपनी नीति की घोषणा की। इसके दो प्रोन्गस हैं। एक देश के भीतर ज़ीरो टॉलरेंस का एटिट्यूड टूवर्ड्स टैररिज्म है और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी दुनिया के देशों को टैररिज्म के खिलाफ मौबिलाइज करने का है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें सफलता पाएगी।

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): I would like to raise one point.

MR. SPEAKER: You may ask for one or two clarifications. I can allow only one or two clarifications.

श्री राजेश पायलट (दौसा) मैंने कल बहुत प्वाइंटिड क्वेश्चन्स पूछे थे। आज बहुत सही ढंग से गृह मंत्री ने कुछ बातें कहीं। हमारा कल यह पूछने का मन था कि मिलिटैसी जम्मू-काश्मीर में स्कबेयर हुई है या नहीं? आपने कहा कि वहां बाहर के लोग ज्यादा और अन्दर के कम आए हैं। घुसपैटिए पिछले तीन साल के मुकाबले इस साल ज्यादा आए हैं। आप रिकॉर्ड देख कर हमें बताएं। १९९९ में घुसपैट ज्यादा से ज्यादा हुआ है। यहाँ ४० परसेंट विदेशी घुसपैटिए आए हैं।

... (व्यवधान)

जब आडवाणी जी विरोधी दल में थे तो छोड़ा में कंटोनमेंट बनाने की बात चलती थी। उसमें पैसा एलाट हुआ लेकिन उसमें क्या प्रगति हुई है? वहाँ कंटोनमेंट बन रहा है या नहीं? इसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया। एन.एस.सी.एन. के साथ बातचीत पिछले तीन साल से चल रही है। क्या संसद का यह पूछने का हक नहीं है कि उसमें क्या प्रगति हुई है? नैगोसिएशन चल रही है। मेरा अन्दाजा यह है कि सरकार की तरफ से सिनसिएरिटी नहीं है। अब इस काम को खत्म करने का मौका मिला है। वह कहीं हाथ से न निकल जाए, इसका आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि इनका समाधान करने का मन है। जैसा आडवाणी जी ने मिजोराम का उदाहरण दिया। सरकार इनिशिएटिव ले और इस नैगोसिएशन को जल्दी सही रास्ते पर लाएँ।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : I could not participate yesterday in the debate as my aircraft was late by 4 1/2 hours.

MR. SPEAKER: Today also you are late.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : I would like to raise three pointed questions and nothing else. My first point is that whether the hon. Home Minister is aware that Barrak Valley which is known as the Island of Peace, is now under terrorist activities and our main victim is the tea industry. Every day there are incidents of kidnappings of Managers and Assistant Managers. The Police is now an ineffective lot. They do not have any army to counter it. Only Army and para-military can do it. I have written to you in this regard. What action are you taking?

I would like to draw your attention to the news item that the Governor of Assam and the Army have said that they would give safe passage to terrorists to go to their respective homes with the idea that there will be some change in their minds. We are now nearing the 31st December. I saw that a Mr. Pillai also gave a statement. I would like to know if it is a fact and if so, what is being done about it.

Thirdly, I understand that you are trying to start negotiations. Will there be some negotiations within the Constitutional framework? Earlier, there were some reservations from the Assam parties that negotiations should not be held in foreign countries. But now all parties are saying that if it is within the framework of the Constitution of India, they have no objection to negotiations even outside

India.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक सैसेटिव सवाल पूछ रहा हूँ

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have already participated in the debate. You can only ask a specific question. Otherwise, it becomes a debate.

SHRI L.K. ADVANI: You can put your question. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I understand, this is an important matter. If you have any questions, you can put them.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जहाँ तक टैरिज्म का सवाल है, भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो इससे परेशान है। अमरीका में और इज्राइल में टैरिज्म है। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से इज्राइल ने अपने आसपास के देशों में टैरिज्म की

kindergarten of terrorism

झील करने की नीति अपनाई है, क्या भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी? हमारे बॉर्डर पर टैरिस्ट्स को तैयार किया गया है या जो प्रशिक्षण शिविर तैयार किये गये हैं, उन शिविरों को नष्ट किया जाये, उनको खत्म किया जाये, इस बारे में हमें सोचना होगा, क्या सरकार इन बातों पर विचार करेगी?

SHRI K.A. SANGTAM (NAGALAND): I put one question on the floor and the reply which I got was that the hon. Minister is not inclined to accept that question. This is very serious because after the attempt on the Chief Minister's life, an intelligence report has been sent to all the important newspapers saying that 14 numbers of AK-47 ammunition empty cases, 11 numbers of 7.62 empty cases and a lot of other items were found when the search of the spot and area was made. Today, why are they declining to give the reply to us? I want to have a reply because it is the privilege of this august House to know.

MR. SPEAKER: What is your question?

श्री के.ए. सांगतम : इस सारे हमले में कौन डायरेक्ट इन्वाल्ड है और इस हमले में एक्शन क्या लिया गया, यह पूछना है? मेरा स्टेट क्वेश्चन है, इसमें पज़ल करने की कोई बात नहीं है।

SHRIMATI KRISHNA BOSE (JADAVPUR): I want to make one proposal. This is very important for the whole nation. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: We have debated this subject for almost four hours and fifteen minutes.

... (Interruptions)

SHRIMATI KRISHNA BOSE : I asked the Home Minister yesterday, apart from strengthening security positions in Jammu and Kashmir, whether they are considering some political negotiations. In the process, we can try to isolate those groups who are openly pro-Pakistan. Are we thinking of being careful with some of the groups who are not blatantly pro-Pakistan so that we do not do anything that would push them into the arms of Pakistan. We should try to get them to the negotiating table. I did not get an answer to this.

श्री प्रियरंजन दासमूंशी (रायगंज) : मैं गृह मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से सरकार का रवैया बताया है। लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने खुद कहा कि त्रिपुरा की समस्या के हल के लिए हमारी बॉर्डर स्टेट्स के साथ बात चल रही है। क्या मैं आपसे आदर के साथ इतना कह सकता हूँ कि त्रिपुरा की समस्या इतनी गंभीर है, आप जल्दी से जल्दी बंगला देश के प्रधान मंत्री के साथ बात करके इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी सफलता मिलेगी।

The exchange of talks between the officials of the paramilitary forces or the exchange of visits of the VIPs between two countries will not bring any solution unless diplomatic intervention is sought.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Sir, I have not got a reply from the Minister.

MR. SPEAKER: The procedure is, discussion under Rule 193 ends with the reply of the Minister. Seeing the importance of the matter, I have allowed some of the Members to seek clarifications. You have already participated in the discussion yesterday.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat. This should not become a debate.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not good. Every time you stand up and seek clarifications.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: राजेश पायलट जी ने आज एक प्वाइंटड सवाल पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कल आपने इसका निज़र किया था, वह यह था कि बहुत सालों से यह डिमांड रही है कि डोडा में एक आर्मी कैम्पेन्स बनाया जाए। वर्षों से वह मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन इस पर तय हो गया है और इसे स्वीकार कर लिया है और उसके लिए अमाउंट भी एलोकेट किया गया था, लेकिन बीच में कारगिल आ गया, इसलिए उसकी प्रगति में शायद कुछ गति नहीं आई है। लेकिन मैं इसे परस्यू करूंगा।

दूसरा सवाल आपने इनफिल्ट्रेशन के बारे में पूछा है। यह सही है कि इनफिल्ट्रेशन हुआ है और इनफिल्ट्रेशन को वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण रोक पाना कठिन है।

लोकन यह कहना कि इस साल सबसे ज्यादा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो अंदाजे आये हैं, वे अलग-अलग आये हैं। अलग-अलग इंटेलेजेंस एजेन्सीज हैं, अलग-अलग आर्मी और स्टेट एजेन्सीज का फर्क है। लोकन इनफिल्ट्रेशन हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। संतोष मोहन जी ने ध्यान दिलाया है कि भारत वैली में इस बार हिंसा हुई है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में छानबीन करूंगा और उनसे जानकारी मांगूंगा। लोकन कदम उन्हें ही उठाने पड़ेंगे। आपने एक सवाल और पूछा कि मिलिटेंट्स के साथ कोई झयलाग है या नहीं? उनके साथ कोई झयलाग नहीं है, चूंकि वे कांस्टीट्यूशन से बंधने को तैयार नहीं रहते हैं। उल्फा के लोग हमेशा सैपरेट असम की बात करते रहते हैं। इस सरकार का मत यह है कि अगर चर्चा करनी है तो चर्चा कांस्टीट्यूशन के भीतर होनी चाहिए। चतुर्वेदी जी ने हमें इनराइल की नकल करने की सलाह दी है। मुझे पता नहीं है कि इनराइल को लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा

... (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम नीरो टोलरेन्स की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां टेररिज्म की जड़े हैं, वहां हमले होने चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कहा

It is a suggestion for action. It is not a question.

सचमुच में अध्यक्ष जी, अगर इस समय सवाल परमिट करते हैं तो वही सवाल परमिट करते हैं जो पहले बहस में उठाये गये हैं और जिनका उत्तर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई खड़ा हो जाए। कृष्णा बोस जी ने सुझाव दिया है कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर भी चर्चा की जाए, वार्ता की जाए। मैंने वार्ता के बारे में कहा कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि अंत में कोई सोल्यूशन निकलता है तो वार्ता से ही निकलता है। लोकन वार्ता कब की जाए और किससे की जाए, इसके लिए हमेशा विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए और वह करते हुए मैं आज कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में जब वहां पर स्थानीय समर्थन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस स्थिति में सब बातों के बारे में सोचना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बॉर्डर फौन्सिंग के बारे में कुछ करना पड़ेगा।

SHRI L.K. ADVANI: Border fencing on the Eastern frontier has been done to a certain extent not in Tripura. But I will pursue it.

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Item No.15. The time allotted for this Bill is two hours.

&nb